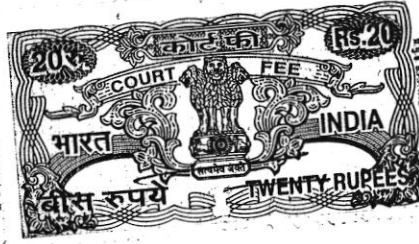


88

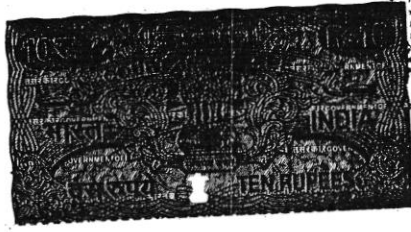


1। अग्रणी/विदिशा/भूपर/2017/4951

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2017 निगरानी



अशफाक उद्दीन पुत्र श्री अमीन उद्दीन  
आयु- 59 वर्ष, जाति- मुस्लिम  
निवासी- ग्राम सीहोरा तहसील कुरवाई  
जिला विदिशा, हाल निवासी- मकान  
नं0 9, अशोका कॉलोनी, ओल्ड लैक व्यू  
होटल के बगल में, नूर महल, भोपाल,  
म0प्र0 —निगरानीकर्ता/रिस्पोंडेन्ट

बनाम

सुशील कुमार पुत्र श्री उमाशंकर  
अग्रवाल आयु- 44 वर्ष, निवासी- शिव  
मंदिर सीहोरा तहसील कुरवाई जिला  
विदिशा, हाल निवासी- बेलविडेशी एवेन्यु  
सनवुड एन-जे, अमेरिका (यू0एस0ए0)

—प्रतिनिगरानीकर्ता/अपीलार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959  
सहपठित म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(3) की कण्डिका  
30 विरुद्ध आदेश दिनांकी 14/11/2017 पारित द्वारा न्यायालय  
अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक  
48/अपील/16-17 निगरानी व उनवान सुशील कुमार बनाम  
अशफाक उद्दीन आदि ।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता/रिस्पोंडेन्ट की ओर से निगरानी निम्न प्रकार

उमाशंकर कादान

8-12-17

~~8-12-17~~

दि० 21-12-17


87/12/17

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- एक/निग0/विदिशा/भू.रा./2017/4951

जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२४/१३/१७	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई जिला विदिशा के द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/अपील/16-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14-11-17 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 19 नियम 2 सी.पी.सी. को इस आधार पर कि प्रकरण में साक्ष्य कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए उनके समक्ष आवेदक ( इस न्यायालय में अनावेदक ) को प्रतिपरीक्षण हेतु तलब किए जाना आवश्यक नहीं माना है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अभी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p>	<p style="text-align: right;"> प्रशा0 सदस्य</p>